|आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार
देहरादून (उत्तराखण्ड)
बुधवार 21.05.2025
समय 0720

मुख्य समाचार :–

- 38वें राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को दिए जाने वाले नगद इनाम के लिए 15 करोड़ रुपए धनराशि जारी।
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनप्रतिनिधियों से भ्रष्टाचार के खिलाफ कतई न बर्दाश्त करने की नीति अपनाने का आग्रह किया।
- सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावण ने कहा– महिला सशक्तिकरण के बिना, विकसित राष्ट्र की संकल्पना अधूरी।
- मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सभी सचिवों को अपने विभागों में ई–ऑफिस लागू करने के निर्देश दिए।

धनराशि **जारी**

38वें राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को उनकी नगद इनाम की धनराशि जल्द मिलने वाला है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि इसके लिए कल शासन की ओर से 15 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि खिलाड़ियों को अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार ने नगद इनाम राशि को दोगुना कर दिया था। खेल मंत्री ने बताया कि अब तक के राष्ट्रीय खेलों के इतिहास में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीतने पर इतनी नगद इनाम राशि किसी भी राज्य में नहीं दी गई है। उन्होंने बताया कि व्यक्तिगत और टीम स्पर्धाओं में प्रदेश के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की संख्या कुल मिलाकर 240 के आसपास है।

आग्रह

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनप्रतिनिधियों से पारदर्शिता, जवाबदेही और ईमानदारी को कार्यशैली का मूल मंत्र बनाने और भ्रष्टाचार के खिलाफ कतई न बर्दाश्त करने की नीति अपनाने का आग्रह किया है। देहरादून में आयोजित 'शहर से संवाद' कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी नगर निगमों और नगर पालिकाओं के महापौरों व अध्यक्षों से बातचीत में कहा कि जनप्रतिनिधि अपनी भूमिका को सिर्फ पद तक सीमित न रखें, बल्कि जनसेवा को एक मिशन मानते हुए काम करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर निकाय किसी भी शहर की आत्मा हैं और उनके माध्यम से ही बुनियादी सुविधाएं जनता तक पहुँचती हैं। उन्होंने जल निकासी, कचरा प्रबंधन, ट्रैफिक और पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दों पर स्थानीय निकायों से सक्रिय भूमिका निभाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने नगर निकाय कार्यालयों को डिजिटल बनाने, रजत जयंती पार्क और वेंडिंग जोन विकसित करने की घोषणा की। साथ ही, भारत सरकार से टाइड फंड को अनटाइड

करने का अनुरोध करने की बात भी कही। श्री धामी ने नगर निगमों में 10, नगर पालिकाओं में 5 और नगर पंचायतों में 3 हाई–टेक हेयर सैलून, पार्लर खोलने के लिए महिला–पुरुषों को प्रशिक्षण देने की योजना की घोषणा भी की। इस दौरान उन्होंने समान नागरिक संहिता, सख्त भू–कानून, नकल विरोधी कानून और भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े कदमों की जानकारी भी साझा की। कार्यक्रम में देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल, नगर विकास सचिव नितेश कुमार झा, नगर आयुक्त नमामि बंसल समेत राज्य भर के 100 से अधिक जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे।

ट्रैफिक समस्या समाधान

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि देहरादून–दिल्ली एलिवेटेड रोड परियोजना अपने अंतिम चरण में है। इसका काम पूरा होने के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी से देहरादून आने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी। उन्होंने यह भी बताया कि देहरादून से बहने वाली दो नदियों– रिस्पना और बिंदाल पर करीब 26 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड बनाई जाएगी, जिससे शहर में जाम की समस्या का समाधान हो सकेगा। छह हजार करोड़ रुपए से अधिक की इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है।

शिलान्यास

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के मांडूवाला स्थित सरस्वती विद्या मन्दिर में छात्रावास का शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये छात्रावास, छात्रों को आवासीय सुविधा प्रदान करने के साथ उनके सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा भारत की स्वतंत्रता के बाद सांस्कृतिक मूल्यों, राष्ट्रवाद की भावना को पुनर्स्थापित करने के लिए सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना की गई। श्री धामी ने हाल ही में संपन्न हुई 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में शत–प्रतिशत परिणाम प्राप्त करने वाले छात्रों को शुभकामनाएं भी दी।

डॉ धन सिंह रावत

सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के बिना विकसित राष्ट्र की संकल्पना अधूरी। उन्होंने ये बात कल अल्मोड़ा में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में "सहकारिता से महिला सशक्तिकरण" विषय पर आयोजित गोष्ठी में कही। उन्होंने कहा कि इसी मूलमंत्र को अपनाते हुए सरकार महिलाओं को आगे लाने का निरंतर प्रयास कर रही है। महिलाओं के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं धरातल पर उतर रहीं हैं। लखपति दीदी कार्यक्रम हो या महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत का आरक्षण, ये सभी महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार उपलब्धियां हैं। उन्होंने कहा कि सहकारिता विभाग के माध्यम से महिलाओं को ऋण देकर उन्हें आत्मनिर्भर करने का प्रयास भी सरकार कर रही है। अब महिलाएं स्वयं घर की मुखिया बन रही हैं। इस अवसर पर डॉ. रावत ने कार्यक्रम में बेहतर कार्य

करने वाले स्वयं सहायता समूहों और महिलाओं को सम्मानित किया। गोष्ठी का आयोजन अल्मोड़ा सहकारी बैंक और सहकारिता विभाग की ओर से किया गया।

ई–ऑफिस

मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सभी सचिवों को अपने–अपने विभागों में ई–ऑफिस लागू किए जाने के निर्देश दिए। कल देहरादून में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सचिव समिति की आयोजित बैठक ये निर्देश दिए। उन्होंने ई–ऑफिस लागू करने में पौड़ी जिले के प्रदर्शन की सराहना करते हुए बाकी जिलों विशेषकर देहरादून, नैनीताल और हरिद्वार को जल्द ई–ऑफिस के माध्यम से कार्यों को किए जाने पर जोर दिया। उन्होंने ई–ऑफिस सिस्टम के अंतर्गत शासन व निदेशालय के मध्य समन्वय को सरल किए जाने की बात भी कही। श्री बर्द्धन ने आईटीडीए के माध्यम से तैयार नए फॉर्मेट में विभागीय वेबसाईटों को अपडेट किए जाने पर बल दिया। साथ ही दैनिक गतिविधियों में कार्मिकों को आ रही समस्याओं के निराकरण के लिए आईटी विभाग द्वारा ई–ऑफिस व वेबसाइट अपडेट के लिए तकनीकी सहायता व प्रशिक्षण उपलब्ध कराने को कहा।

मदरसे

उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड ने छात्रों को सेना के शौर्य से अवगत कराने के लिए 'ऑपरेशन सिंदूर' को पाठ्यक्रम में शामिल करने का निर्णया लिया है। इससे 50 हजार से ज्यादा मदरसा छात्रों को भारतीय सेना के पराक्रम की जानकारी मिलेगी। प्रदेश सरकार की पहल पर मदरसों के छात्रों को देशभक्ति और सेना के शौर्य से जोड़ने के लिए मदरसा बोर्ड ने एक अहम कदम उठाया है। उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती समून काशमी के मुताबिक, यह नया विषय इंटरमीडिएट की कक्षाओं तक पढ़ाया जाएगा।

आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर––

आज के समाचार पत्रों ने अलग–अलग ख़बरों को प्राथमिकता दी है।

जल, ऊर्जा और शिक्षा को पैंतालीस हजार करोड़ रुपए जरूरी। इस शीर्षक के साथ हिंदुस्तान समाचार पत्र लिखता है– धामी सरकार ने सोलहवें वित्त आयोग को सौंपा बुनियादी क्षेत्र की जरूरत का ब्यौरा।

जून में आर–पार होगी ऋषिकेश–कर्णप्रयाग रेल परियोजना की गुलर–व्यासी सुरंग, दैनिक जागरण समाचार पत्र की सुर्खी है। समाचार पत्र के अनुसार इस परियोजना के तहत अब तक अड़तीस सुरंग आर–पार हो चुकी हैं।

एक देश एक चुनाव बिल पर सुझाव लेने उत्तराखंड पहुंची संयुक्त सदस्य समिति। इस शीर्षक के सात अमर उजाला समाचार पत्र लिखता है– समिति राज्यपाल, मुख्यमंत्री, स्पीकर, सियासी दलों व प्रबुद्ध जनों से दो दिन करेगी चर्चा।

पिरूल बनेगा ग्रामीणों की आय का साधन, वनाग्नि घटनाओं पर लगेगी लगाम। राष्ट्रीय सहारा समाचार पत्र ने इस शीर्षक के साथ ख़बर दी है कि उत्तरकाशी जिले में अपर यमुना वन प्रभाग के तहत इस वर्ष में पहले चरण में सैंतीस वन पंचायतों के माध्यम से पिरूल एकत्रीकरण का कार्य किया जा रहा है।